अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी एवं सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका
Peer Reviewed Refereed शोध पत्रिका
ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 12-Issue 04, (Oct-Dec 2024)

राष्ट्रीय आजीविका मिशन का गरीबी उन्मूलन में योगदान (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

शोधार्थी – जितेन्द्र कुमार कामले (समाजकार्य)
शोध निर्देशक – डॉ. डी. के. वर्मा (डीन–एटीपी)
शोध केंद्र – समाज विज्ञान एवं प्रबंधन अध्ययनशाला
डॉ.बी.आर.अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,डॉ. अंबेडकर नगर, (महू), इंदौर,म.प्र.

1. **सारांश** –राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन भी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। खरगोन जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आजीविका मिशन के सकारात्मक प्रभावित किया है। इस कार्यक्रम को अमल में लाने के लिये पंचायती राज संस्थाओं को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, जैसे कि इस प्रकार राष्ट्रीय आजीविका मिशन गरीबी उन्मूलन को दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें एसजीएसवाई की खामियां दूर की गई है। उसी प्रकार निर्धन से निर्धन अर्थात अति निर्धन व्यक्ति की पहचान करना और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें संगठित करना एवं स्वयं सहायता समूहों को परिसंघों में संगठित करना एवं उन्हें आवश्यक भूमिका एवं बुनियादी सुविधायें प्रदान करना है। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक योजनाओं में स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों की प्राथमिकता के आधार पर उनकी जरूरतों को शामिल किया गया है। इन उद्देश्यों के लिये आवश्यक विधियों का आंवटन तथा विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बिठाना गया है। इस मिशन की सफलता और विफलता उन ग्रामीणों में जागरूकता के स्तर पर भी निर्भर करती है। अत' इस कार्य को करने के लिये एक जोरदार जागरूकता अभियान की जरूरत है, तभी लाभार्थी अपनी गरीबी से निपटने के लिये नये अवसर पाने में सफल होंगे।

प्रस्तावना –

राष्ट्रीय आजीविका मिशन जिसका पूरा नाम National Rural Livelihood Mission जिसे NRLM के नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसे संचालित किया जाता है। स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को पुनर्गठित कर 1 अप्रैल 2013 को राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरूआत की गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब लोगों के कल्याण के लिये बनाई गई थी। इस योजना को बनाने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करना है, जिससे उन्हें शहरों में रोजगार के लिये पलायन न करना पडें।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 12-Issue 04, (Oct-Dec 2024)

राष्ट्रीय आजीविका मिशन केंद्र के राज्यों के नाम पर बनाया गया है। जो इस प्रकार से है–

क्रं.	राज्य	राष्ट्रीय आजीविका मिशन का नाम
1.	उत्तरप्रदेश	उत्तरप्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन (यूपीएसडीएम)
2.	पश्चिमी बंगाल	पश्चिमी बंगाल सोसायटी फॉर स्किल डेवलपमेंट (पीबीएसएसडी)
3.	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ स्टेट रूरल लिवींगहुड मिशन
4.	केरल	कुदुमबाश्री
5.	आंध्रप्रदेश	ईजीएमएम
6.	तमिलनाडु	तमिलनाडु कार्पोरेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ वूमेन लिमिटेड
7.	तेलंगाना	ईजीएमए
8.	पंजाब	पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन
9.	राजस्थान	आरएसएलएम
10.	हरियाणा	हिमायेट मिशन मेंनेजमेंट यूनिट(एचएसआरएलएम)
11.	जम्मू कश्मीर	जम्मू एण्ड कश्मीर स्अेट रूरल लिविलीहुड मिशन(जेकेएसआरएलएम)
	उत्तराखंड	यूएसआरएम
	उडीसा	उडीसा रूरल डेवलपमेंट एण्ड मार्केटिंग सोसायटी
	महाराष्ट्र	महाराष्ट स्टेट रूरल लिविंगहुड मिशन
	गुजरात	गुजरात लिविंगहुड प्रमोशन कंपनी (जीएलपीसी)
	मध्यप्रदेश	एमपी स्टेट रूरल लिविंगहुड मिशन
	असम	एएसआरएलएम
	त्रिपुरा	त्रिपुरा रूरल लिविंगहुड मिशन सोसायटी
	बिहार	बिहार लिविंगहुड प्रमोशन कंपनी सोसायटी (बीएलपीसी)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 12-Issue 04, (Oct-Dec 2024)

इन समूहों के माध्यम से देश की ग्रामीण महिलाओं को एक नई पहचान मिली है। प्रदेश के विभिन्न अंचलो में पहाडी, घाटियों, जंगलों एवं छोटी–बडी नदियों के किनारे बसने वाली जनजाति सदियों से चली आ रही है। ये लोग पारंपरिक रूप से कृषि से जुडे समुदाय होने के कारण वनो से उत्पन्न उपजों को बेचकर एवं मेहनत–मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते है। कडी मेहनत करने के बावजूद ये कभी गरीबी से मुक्त नहीं हो पाये। इसके लिये सरकार ने ग्रामीण विकास के लिये अनेकों परियोजनायें चलाई। प्रत्येक योजनाओं का अपना एक विशिष्ट लक्ष्य एवं उद्देश्य के लिये बनाई गई।

ग्रामीण आजीविका मिशन भी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। खरगोन जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आजीविका मिशन के सकारात्मक प्रभावित किया है। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अनेक लोगों को पशुधन से लाभांवित देखते हुये जनजातिय परिवारों को बकरी पालन से जोडा गया। इसके अलावा गांवों के आसपास बडे–बडे तालाब होने के कारण मछली पालने को प्रोत्साहित किया गया। इसके लिये मतस्य पालन विभाग के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया।

राष्ट्रीय आजीविका मिशन को बनाने के कई महत्वपूर्ण उद्देश्य है जो इस प्रकार से है–

- आजीविका मिशन को बनाने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक सामाजिक एकजुटता बनाये रखना है।
- इसके अलावा गरीबों की सहभागी पहचान बनाने पर जोर दिया गया है। उनके लिये अनेक प्रकार की संस्थाओं के निर्माण करने पर जोर दिया गया है।
- यह गरीबों के सभी स्वयं सहायता समूहों और परिसंघों को मजबूत बनाने का कार्य करता है।
- एनआरएलएम में प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर जोर दिया गया है।
- यह रिवोल्विंग फंड के साथ–साथ सामुदायिक निवेशक फंड भी प्रदान करता है।
- एनआरएलएम का लक्ष्य सार्वजनिक वित्तीय समावेशक (यूनिवर्सल फाइनेंसल इनक्लुजन) है।
- इस कार्यक्रम में ब्याज पर अनुदान देने का भी प्रावधान है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें राज्यों को भी भागीदार बनाया गया है। केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषक का अनुपात 75:25 का है जबकि उत्तर–पूर्वी राज्यों में इसका अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है।
- एनआरएलएम के तहत भागीदारों के प्रशिक्षण के आधार पर ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं (आरएसईटी.आई) की स्थापना की गई है।
- इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर वांछित क्रियांवयन तंत्र की स्थापना की है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 12-Issue 04, (Oct-Dec 2024)

इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम को अमल में लाने के लिये पंचायती राज संस्थाओं को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। जो इस प्रकार से है–

1. निर्धन से निर्धन अर्थात अति निर्धन व्यक्ति की पहचान करना और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें संगठित करना है।

2. स्वयं सहायता समूहों को परिसंघों में संगठित करना एवं उन्हें आवश्यक भूमिका एवं बुनियादी सुविधायें प्रदान करना है।

3. पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक योजनाओं में स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघों की प्राथमिकता के आधार पर उनकी जरूरतों को शामिल किया गया है।

4. इन उद्देश्यों के लिये आवश्यक विधियों का आंवटन तथा विभिन्न विभागों के साथ तालमेल बिठाना है।

5. इस प्रकार राष्ट्रीय आजीविका मिशन गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें एसजीएसवाई की खामियां दूर की गई है।

6. इस मिशन की सफलता और विफलता उन ग्रामीणों में जागरूकता के स्तर पर भी निभर करती है। अतः इस कार्य को करने के लिये एक जोरदार जागरूकता अभियान की जरूरत है, तभी लाभार्थी अपनी गरीबी से निपटने के लिये नये अवसर पाने में सफल होंगे।

अध्ययन का उद्देश्यः–

राष्ट्रीय आजीविका मिशन और अनुसूचित जनजाति गरीब परिवारों का अध्ययन, मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में किया जाना है।

शोध प्रविधि –

प्रविधि –

अध्ययन क्षेत्र के लिये म.प्र. के खरगोन जिले का चयन किया गया है। जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों पर प्रभाव– एक अध्ययन लिया गया है।

अध्ययन क्षेत्र –

अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के स्वयं सहायता समूह से अनुसूचित जनजाति परिवारों को सर्वे के किया गया है।

अध्ययन का समग्र –

म.प्र. के खरगोन जिले के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से लाभांवित अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार अध्ययन को समग्र के रूप में लिया गया है।

अध्ययन की इकाई –

म.प्र. के खरगोन जिले के ग्रामीण आजीविका मिशन से अनुसूचित जनजाति के गरीब हितग्राही उत्तरदाता का एक परिवार अध्ययन की इकाई है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 12-Issue 04, (Oct-Dec 2024)

निदर्शन विधि –

प्रस्तुत अध्ययन में खरगोन जिले के 350 परिवारों का चयन किया गया है और अनुसूचित जनजाति परिवारों का सर्वे किया गया है। जिसमें प्राप्त आकडों का विश्लेषण किया गया है। सोद्देश्यपूर्ण विधि का उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से खरगोन जिले के समूह के माध्यम से वास्तविक स्थिति का पता लगा कर सामने लाने की कोशिश की गई है।

प्राथमिक संकलन – पाथमिक संकलन साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नावली, समूह चचर्य के माध्यम से उत्तरदाताओं कीसे जानकारी प्राप्त कर किया गया है।

द्वितीयक संकलन – पत्र–पत्रिकाओं, समाचार–पत्र, शासकीय–अशासकीय विभागों द्वारा प्रकाशित प्रकाशन आदि से किया गया है।

तथ्यों का विश्लेषण –

तथ्यों का विश्लेषण एस.पी.एस.एस के माध्यम से दण्डरेखीय आरेख एवं सारिणीयन के माध्यम से किया गया है।

सारिणी क्रं. –1

मिशन से गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल करने में कितनी सफल हुई है? से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	बहुत सफल	190	54.2
2.	असफल	70	20.0
3.	आंशिक	90	25.8
	योग	350	100.0

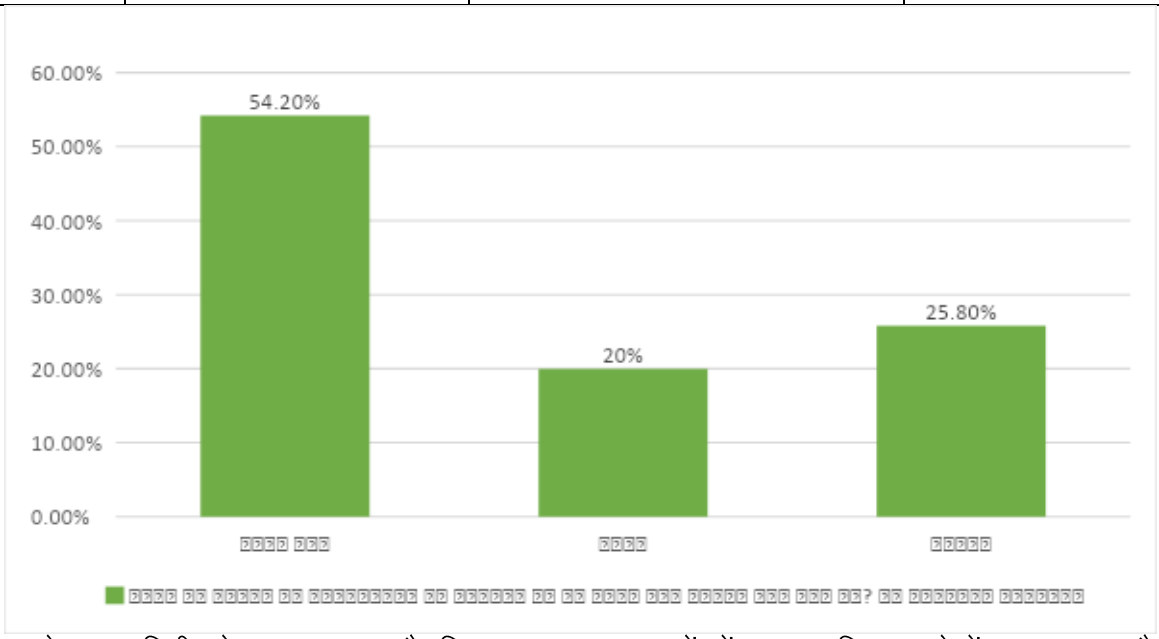

उपरोक्त सारिणी से पता चलता है कि 350 उत्तरदाताओं में 54.2 प्रतिशत लोगों का कहना है कि मिशन ये गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सफल रहा है, जो कि सर्वाधिक है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 12-Issue 04, (Oct-Dec 2024)

जबकि 20 प्रतिशत लोगों का मानना है कि असफल रहा है और 25.80 प्रतिशत लोगों का मानना है कि आंशिक सफल हुआ है।

अतः इससे स्पष्ट है कि 54.20 प्रतिशत हितग्राही स्वीकार करते है कि काफी हद तक यह मिशन गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या को हल करने में सफल रहा है।

सारिणी क्रं. –2

योजना से रोजगार में वृद्धि स संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	हां	210	60
2.	नहीं	140	40
	योग	350	100

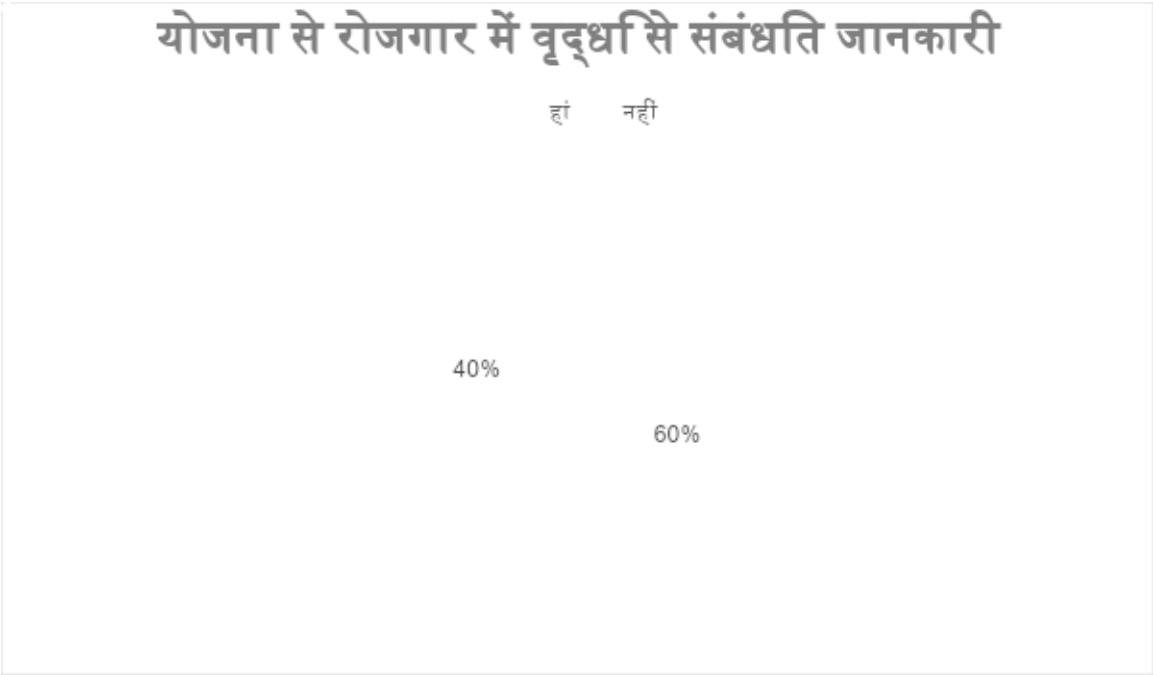

उपरोक्त सारिणी में हितग्राही 350 उत्तरदारताओं में से 60 प्रतिशत लोगों का कहना है कि योजना से रोजगार में वृद्धि हुई है, जबकि 40 प्रतिशत लोगों का कहना है कि योजना से रोजगार में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इससे स्पष्ट हे कि खरगोन जिले के अधिकांश हितग्राही परिवारों को रोजगार प्राप्त हुये है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 12-Issue 04, (Oct-Dec 2024)

सारिणी क्रं. –3

मिशन में स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित गतिविधियां से संबंधित जानकारी

क्र.	उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	कृषि उपकरण	85	24.2
2.	पशुधन	61	17.5
3.	लघु एवं कुटीर उद्योग	182	52.0
4.	वनों के माध्यम से	12	3.5
5.	अन्य	10	2.8
	योग	350	100.0

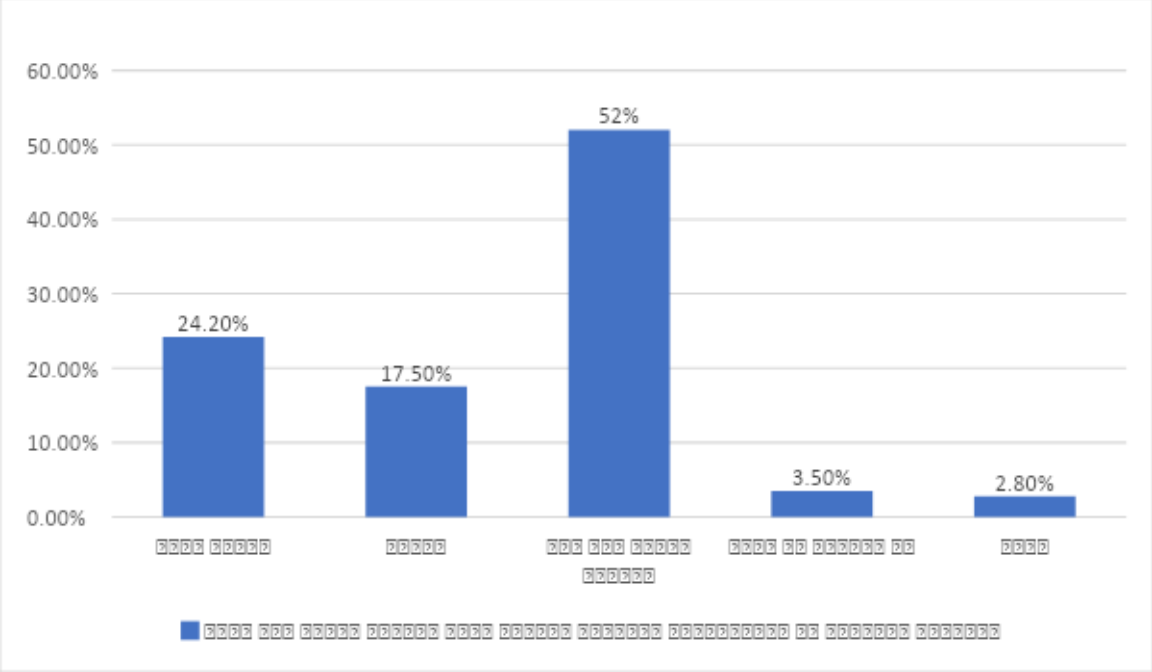

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट होता है कि 350 उत्तरदाताओं में से 24.2 प्रतिशत कृषि उपकरण, 17.50 प्रतिशत लोग पशुधन खरीदने में सर्वाधिक 52 प्रतिशत लोग लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करने में, 3. 50 प्रतिशत लोग वनों के माध्यम से एवं 2.80 प्रतिशत लोग अन्य गतिविधियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों में भाग ले रहे है।

अतः इससे स्पष्ट है कि अधिकतर उत्तरदाता कृषि उपकरण संबंधित संचालित गतिविधियों में भाग लेते है।

ISSN: 2348–2605 Impact Factor: 7.789 Volume 12-Issue 04, (Oct-Dec 2024)

निष्कर्ष –

- उपरोक्त शोध अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलते है कि खरगोन जिले में इस मिशन काफी हद तक सफल रहा है।
- खरगोन जिले के अधिकांश लोगों को रोजगार प्राप्त हुये है जिससे इनका सामाजिक, आर्थिक स्तर बढा है।
- खरगोन जिले के अधिकांश उत्तरदाता परिवार इस मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित गतिविधियों में भाग लेते है।

सुझाव –

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन करना चाहिये।
2. सदस्यों को उचित प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है।
3. गांवों में मिशन के अंतर्गत बहुत कम राशि का अनुदान दिया जाता ह, इसलिये अनुदान राशि को बढाना अति आवश्यक है।
4. इस मिशन के अंतर्गत अधिक से अधिक छोटे–बडे लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने के लिये लोगों को प्रेरित करना चाहिए।
5. राष्ट्रीय आजीविका मिशन के रूप में गरीबी उन्मूलन के नये–नये उपाय अपनाना अति आवश्यक है।

संदर्भ–

- सिंह बैजनाथ (2011), 'सामुदायिक ग्रामीण विकास' निदेश, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, वंसत कुंज, नई दिल्ली
- बेवसाइट– डबलु. डब्लु.एन.आर.एम.एल
- ग्रामीण विकास विभाग वार्षिक रिपोर्ट (2011)
- पंचायत राज अपडेट (2013), 'राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सामने भावी चुनौतिया' इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साईंसेस, नई दिल्ली
- जैन सविता, (2014), 'ग्राम संगठन' मार्गदर्शिका, म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन